

ऊपरी पुलों तथा नीचे के पुलों का निर्माण

*१८. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई स्थानों में रेल के ऊपरी पुल धीरे नीचे के पुलों के निर्माण की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न खंडों के कितने स्थानों से यह मांग की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है कि एक वर्ष में कितने नीचे के या ऊपर के पुल बनाये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना क्या है ?

रेलवे उप मंत्री (श्री से० बे० राम-स्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) अभी इसके बारे में सूचना मौजूद नहीं है और रेलो से मगानी पडगी ।

(ग) और (घ) जी नहीं । जब कभी राज्य सरकारें रेल-प्रशासन से रेलवे लाइनों के ऊपर या नीचे पुल बनाने के लिये कहती हैं और वर्तमान नियमों के अनुसार अपने हिस्से का खर्च देने को तैयार हो जाती हैं, तो उनकी बात तुरन्त मान ली जाती है । राज्य सरकारों से जवाब आने में कुछ समय लगता है, इसलिये इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता कि एक साल में कितने पुल बनाये जायें । लेकिन ज्यों ही राज्य सरकार योजना (Plan) उसके अनुमानित खर्च और अपने हिस्से का खर्च उठाने की मजूरी दे देती है, रेल प्रशासन अपने निर्माण कार्यक्रम (Works Programme) में इस काम के लिये जरूरी रकम की व्यवस्था करते हैं और काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाता है ।

साधारण में आत्मनिर्भरता

*१००. श्री साब.वाला :

{ श्री का० बे० भालबीय

क्या साधारण तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण के मामले में कितने राज्य आत्मनिर्भर हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों के आत्मनिर्भर न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन कारणों की कोई जांच की गई है और इन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

साधारण तथा कृषि मंत्री (श्री ए० प्र० जैन) : (क) सामान्यतः आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में अन्न की उपज खपत से अधिक होती है, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्रास तथा मैसूर आत्मनिर्भर हैं ।

(ख) से (घ). आत्मनिर्भरता समूचे देश के लिये ही प्राप्त करनी है । प्रत्येक राज्य में चाहे वह आत्मनिर्भर है या नहीं, साधारण की उपज में उन्नति के लिये गुंजाइश है । परन्तु हो सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र अथवा राज्य आत्मनिर्भरता प्राप्त न कर सके । प्रत्येक राज्य की समस्याओं का निरन्तर निरीक्षण किया जा रहा है, और खेती की उपज को बढ़ाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं ।

Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

*101 Shri Daljit Singh: Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 2980 on the 27th September, 1958 and state the progress made so far in filling up the quota reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Railway Protection Force on the Central Railway?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): In Class III the deficiency is 4 of Scheduled Castes and 5 of Scheduled Tribes. In Class IV the deficiency is in the category of Scheduled Tribes only to the extent of 141.

Efforts are being made to eradicate the shortfall in both the classes by the end of the current year 1958-59 as stated earlier.

Tungabhadra Project

*102 { Shri Agadi:
Shri Siddananjappa.

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state

(a) the actual area brought under irrigation under the Tungabhadra Project Left Bank development scheme excluding the previously cultivated area under the old Anicuts, and

(b) the total amount spent so far, for the Project and development of both sides of the Ayacut areas?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) An area of 39,930 acres was actually brought under irrigation upto the end of December, 1958.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Berapoly River Project in Kerala

*103. { Shri A. K. Gopalan:
Shri Kunhan.

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Deputy Minister for Irrigation and Power had recently visited the Berapoly River Project site in Kerala,

(b) if so, the outcome of the discussions held by him with the Kerala and Mysore State Government, and

(c) whether it is proposed to take

up the project during the Second Five Year Plan itself?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) Yes, Sir

(b) He held no discussions with the representatives of Mysore Government. The Minister for Irrigation and Power, Kerala State accompanied the Deputy Minister to the Berapoly River Valley Project site in Kerala and generally explained to him the broad aspects of the scheme. He explained to him how this scheme would irrigate the Malabar Area in Kerala. He also indicated that it would also be a cheap power project.

(c) No, Sir

"Demands Day" by Posts and Telegraphs Employees

*104 { Shri Rajendra Singh:
Shri Ram Krishan:

Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Federal Council of the National Federation of Post and Telegraph Employees' Union has resolved to observe "Demands Day", and

(b) if so, what are their demands?

The Minister of Transport and Communications (Shri S. K. Patil): (a) No intimation has been received from the National Federation of P & T Employees. It is, however, understood that they have decided to observe 11th February 1959 as "Demands Day".

(b) The demands are

- (1) Immediate grant of 2nd instalment of interim relief
- (2) Early publication of the Pay Commission's Report
- (3) Repeal of Rules 4(a) and 4(b) of the Govt Servants Conduct Rules
- (4) Re-drafting of Government Servants Conduct Rules